शहरः दिल्ली

राज्यः नई दिल्ली

श्रेणीः कैपिटल, टायर 1

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) दिल्ली राज्य के तीन सांविधिक शहरी निकायों में से एक है, तथा अन्य दो हैं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तथा दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)। एनडीएमसी, दिल्ली महानगर के शहरी बसावट के अंतर्गत आता है और चूंकि यह शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है, इसे संयुक्त तौर पर स्थानीय नगरपालिका के साथ-साथ राज्य व संघीय सरकारों द्वारा अभिशासित किया जाता है। एनडीएमसी के भीतर क्षेत्र दिल्ली का मध्य हिस्सा आता है जिसे ब्रिटिश वास्तुविद् सर एडविन लुटिएन्स द्वारा ब्रिटिश भारतीय राजधानी के तौर पर नियोजित और विकसित किया गया था और इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। आज, यह क्षेत्र भारत सरकार की सीट बनी हुई है, और यहां आज भी सरकारी कार्यालय तथा राजनयिक मिशन्स स्थित हैं। हालांकि नई दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, एनडीएमसी के कुछ हिस्से वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़, और जनसंख्या की अधिकता जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं।

1. जनसांख्यिकी प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	257803	16368899	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)	16349831		
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)			
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	-1.59	2.38	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	42.74		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*	#		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	6032		
साक्षरता दर (%)	89.83	86.32	84.11

अनुसूचित जाति (%)	19.24	16.68	12.60
अनुसूचित जनजाति (%)	0.00	0.00	2.77
युवा, 15-24 वर्ष (%)	21.88	20.42	19.68
स्लम जनसंख्या (%)	7.76	1.12	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	73.53	65.95	65.27

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#एक से अधिक जिले में फैले हुए शहरी स्थानीय निकाय

2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	**शहर (नगर निगम)**	**राज्य (शहरी)**	**भारत (शहरी)**
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (रु.)*	112510	112510	रु. 35,947[a]
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	0.87	9.8	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	2.03	3.5	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	37.30	33.7	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)*** स्व नियोजितः नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारीः अनौपचारिक श्रम।	 19.37 77.14 3.49	 34.8 61.5 3.7	 42.0 43.4 14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			

प्राथमिक द्वितीय तृतीयक	0.00 41.48 58.52	0.0 26.8 73.1	7.5 34.2 58.3
प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			
व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	16.43	24.9	15.8
व्यवसाय	0.00	8.8	8.8
तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर	6.07	7.5	6.7
क्लर्क	12.08	8.3	5.0
सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक	8.51	11.6	14.7
कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक	0.00	0.0	4.6
शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक	17.47	15.9	19.2
प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स)	24.95	9.8	9.2
एलिमेंटरी व्यवसाय	14.50	13.0	16.1
श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं	0.00	0.2	0.1
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	लागू नहीं		
प्रमुख उद्योग##	धातु- एल्यूमीनियम और पीतल, तांबा, लोहा और इस्पात ऑटोमोबाइल, बाईसाइकिल और इसके हिस्से के अन्य उत्पाद गैर धातु- ज्ञान आधारित उद्योग (शोध एवं विकास केंद्र, निजी विश्वविद्यालय) रबर, प्लास्टिक और		

	पेट्रोलियम आधारित		
अनुमोदित एसईजेड की संख्या	1	3	413

नोटः 2011-12, 2012-13, 2013-14 का 3 वर्ष औसत

स्रोतः *सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की यूनिट लेबल डाटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68वां राउंड, 2011-12

***राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68वां राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

∞ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (डिनोमिनेशन)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	98.10	75.81	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	98.82	99.14	92.68
घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	85.03	86.05	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	97.06	96.04	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	27.14	17.95	8.27
कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का	16.48	11.56	10.40

प्रतिशत			
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	62.65	68.13	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%) स्वामित्व किराए पर	 12.08 68.25	 67.90 28.49	 69.16 27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	36.68	30.87	32.94
संकेतक	**शहर (नगर निगम)**		
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*			
प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*			
प्राथमिक			
माध्यमिक			
द्वितीयक			
महाविद्यालय			

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

4. राजनीतिक प्रोफाइलः नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा

शासन की वास्तुकला *चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना। पदानुक्रम के संकेत दें।*	दिल्ली में शहरी प्रबंधन हेतु संस्थागत संरचना के अभिकरणों की काफी बहुलता हैं, केन्द्र तथा राज्य दोनों के। इनके द्वारा शहरी अधोसंरचना तथा इसके प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों की देखरेख भी की जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के 5 शहरी स्थानीय निकायों में से एक है। केन्द्र सरकार ने ज्यादातर नियंत्रण शक्तियों को

	एनडीएमसी में बनाए रखा हैं, केवल इसे छोड़कर कि एनसीटी दिल्ली की सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों के माध्यम से समिति के लिए विवेकाधीन कार्यों को निर्दिष्ट कर सकती है। जीएनसीटीडी भी समिति की लेखा को लेखापरीक्षित करा सकती है। अध्यक्ष जो कि एनडीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, एनसीटी के मुख्यमंत्री के परामर्श में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एनडीएमसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न सामाजिक, सांस्कृति, शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाओं को भी सुनिश्चित करता है, खासकर सरकारी/नगरीय निकायों के कर्मचारियों तथा समाज के अन्य कमजोर तबकों के लिए। शायद देश में यही एक नगरपालिका है जो बिजली और पानी की आपूर्ति करता है तथा इसके विवेकाधीन कार्यों में शामिल हैं खेल, कला, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देना, पुस्तकालयों का अनुरक्षण, बुजुर्गों, मानसिक कमजोर व श्रवण बाधितों की देखभाल करना। यह कामकाजी महिलाओं, आवास की समस्याओं तथा सामाजिक सुविधाओं जैसे कि बरात घर तथा सामुदायिक केन्द्रों की देखरेख करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की स्थापना वर्ष 1957 में हुई, जो कि एक निगमित निकाय है। डीडीए के कार्यों व शक्तियों में शामिल हैं दिल्ली के वर्तमान और भावी विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना; योजनाएं तैयार करना तथा संबंधित प्राधिकारी विभागों व अभिकरणों को कृषि, बागवानी, फूलो की खेती, वानिकी, परिवहन, संचार, स्कूली शिक्षा इत्यादि के विकास की योजनाओं को हाथ में लेने हेतु सलाह देना; शहर के निर्माण हेतु अधिग्रहण, अभिग्रहण, प्रबंधन तथा संपत्ति के निबटान के हिस्से के तौर पर संस्थागत एवं औद्योगिक विकास; भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन, यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी तथा विभिन्न स्थानों पर निकासी नालियों की देखरेख करता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), एनसीटी में प्राथमिक अभिकरण के तौर पर, दिल्ली में जल एवं वायु प्रदूषण की सुरक्षा एवं नियंत्रण से जुड़े विनियामक कार्यों की पूर्ति करता है।

	दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरण डिजाइन के सौंदर्य की गुणवत्ता को बनाए रखने में केन्द्र सरकार को परामर्श प्रदान करने व स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन देने के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। स्थानीय निकायों को सभी निर्माण एवं अभियांत्रिकी परिचालनों व विकास के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने के पूर्व उन्हें आयोग को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) किसी क्षेत्र हेतु अंतर-प्रादेशिक क्षेत्रीय विकास नियोजन का एक अनूठा उदाहरण है, जो कि तीन राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 15 जिलों से अधिक में 33500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और राष्ट्रीय राजधानी इसका केन्द्र है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का गठन क्षेत्र के संतुलित तथा सामन्जस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख तर्काधार के साथ, तथा अधिक से अधिक आर्थिक विकास की दिशा में संतुलित एवं स्थानिक उन्मुख मार्गों को प्रवाहित करते हुए बेतरतीब व अनियोजित शहरी विकास को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) क्षेत्रीय योजना तथा कार्यात्मक योजनाओं को तैयार करने; सहभागी राज्यों के माध्यम से योजनाओं कार्यान्वयन व क्रियान्वयन में समन्वय करने; क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उपक्षेत्रीय योजना तथा परियोजना नियोजन की समीक्षा व कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) कच्चे पानी के प्रापण, उपचार और जल आपूर्ति व इससे जुड़े कार्यों के जवाबदेह संवितरण के लिए जिम्मेदार है। एनडीएमसी हेतु प्रशोधित जल का सृजन और आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। एनडीएमसी को दिल्ली जल बोर्ड से कई जलाशयों से भारी मात्रा में आपूर्ति प्राप्त हो रही है। चूंकि दिल्ली जल बोर्ड एनडीएमसी को आवश्यक मात्रा के दबाव के साथ परिशोधित जल की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिससे की कमी को पूरा किया जा सके, एनडीएमसी ने 100 ट्यूब वेल्स तथा 700 डीप वेल हैंडपंप प्रदान किए हैं।

	डीजेबी अपशिष्ट जल के एकत्रण, परिवहन, उपचार तथा निबटान के लिए और सीवर प्रणाली के परिचालन व अनुरक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।
<u>निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.</u>	लागू नहीं
<u>निर्वाचन विवरण*</u> *चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबंद्धता, मुख्य मंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।*	दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें 14 फरवरी 2015 को निर्वाचित किया गया था। जून 2015 से श्री नरेश कुमार आयुक्त है।

स्रोतः *संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यनिष्पादन

क्रेडिट और कर

शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 तक)* लागू नहीं	एए
संपत्ति कर#	कवरेज (%): 85 से ऊपर संग्रह क्षमता (%): 82 राशि (रु.): 300.00 करोड़ (2013-14)

स्रोतः *www.jnnurm.nic.in

#रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

शहरी स्थानीय निकायों में ई-शासन एवं कम्प्यूटरीकरण

सुधार	**स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)**
संपत्ति कर*	कार्यान्वित

लेखांकन*	कार्यान्वित
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	कार्यान्वित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	कार्यान्वित
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	कार्यान्वित
निर्माण योजना अनुमोदन*	कार्यान्वित
ई-प्रापण*	कार्यान्वित
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटिजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	केवल सीएफसी पर
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	हाँ
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या है#	एनआईसी
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं#	हाँ
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते है?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ
74वैं सीएए का कार्यान्वयन#	5 कार्यों को अभी ट्रान्सफर किया जा रहा है। स्लम सुधार और उन्नयन, शहरी गरीबी उन्मूलन, अंत्येष्टि और कब्रिस्तान, अंतिम संस्कार, श्मशान और बिजली शवदाहगृह, पशु पाउंड, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, बूचड़खानों और चमड़े के कारखानों का विनियमन

नोटः शहरी स्थानीय निकाय में ई-गवर्नेंस के मॉड्यूल कार्यान्वित

स्रोतः https://www.ndmc.gov.in

*सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षैतिज नेटवर्कों की सूची।	• उत्कृष्टता-गोल्ड 2014 के लिए स्कॉच अवार्ड • उत्कृष्टताः सर्वश्रेष्ठ ट्रांजिट परियोजना (2008) के लिए जेएनएनयूआरएम पुरस्कार

6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

वित्तीय

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %	88.63	77.79	67.77

वित्तीय स्थिति#		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण (लाख रु. में)	आय	व्यय
2009-10	194461.11	193570.26
2010-11	169119.08	152336.47
2011-12	137719.74	130055.91
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@		

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

@जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट

पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	16
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	

स्रोतः *प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

7. क्षमताः ट्रैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी			
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	लागू नहीं			
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी	लागू नहीं			
परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	लागू नहीं			
परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (लाख रु. में)	कुल स्वीकृत परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी
	लागू नहीं			

केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)	लागू नहीं			
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)	लागू नहीं			
उपयोग किया गया वित्त (प्रतिशत)	लागू नहीं			

स्रोतः www.jnnurm.nic.in (नवम्बर, 2015 तक पहुंच)

शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकत्रीकरण	स्थिति, टिप्पणी
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)	
अमृत	*शहर अमृत मिशन के तहत शामिल है। राज्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जा चुकी है।*
जेएनएनयूआरएम	*शहर जेएनएनयूआरएम के घटक तहत कवर था।*
एनयूआईएस	
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	

स्रोतः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार